



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

1408  
571198

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8, 1997 (कृति 17, 1919)  
(No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8, 1997 (KARTIKA 17, 1919)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, नियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . . . . .	पृष्ठ 697	भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के हिस्से अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . . . .	1027	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *	
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . . . .	5	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निबंधक और महाभेक्षा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . .	1017
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . . . .	1693	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . . . .	1509
भाग II—खण्ड 1—सांविधिक, अध्यादेश और नियम . . . . .	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य प्रायुक्तों के अधिकार के अधीन प्रयत्न द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . .	0
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और नियमों का हिन्दी भाषा में अधिकृत पाठ . . . . .	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं । . . . .	2493
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . . . .	*	भाग IV—सरकारी व्यक्तियों और गैरसरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . . . .	351
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं) । . . . .	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला प्रमाणपत्र *	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . . . .	*		

\* आंकड़े प्रोत्त नहीं हुए ।

## CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	697	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	1027	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	5	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	1017
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	1693	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	1509
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	3493
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by private Individuals and private Bodies . . . . .	351
PART II—SECTION 2—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi . . . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*		

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्तूबर 1997

संकल्प

के निदेशक तथा एन. एस. एस. ओ. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके सदस्य हैं।

विभाग में एक असांख्यिक, उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति भी है जिसे खाद्य पोषाहार बोर्ड कहा जाता है जिसकी स्थापना भारत के राजपत्र में प्रकाशित 24 अप्रैल, 1964 के संकल्प संख्या 6(10)/63-तकनीकी-1 के अनुसार की गई थी और यह समिति सचिव (महिला बाल विकास) की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। 1963-64 में खाद्य एवं पोषाहार स्कन्ध को खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड एवं (प्रभाग) के रूप में पुनः गठित किया गया, जो खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड (समिति) के सचिवालय और कार्यकारी स्कन्ध के रूप में कार्य करता था। खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है और समय की आवश्यकता के अनुसार इसके कार्यों को पुनर्भाषित किया गया है पिछली बार बोर्ड का पुनर्गठन 1993 में किया गया था, जिसका कार्यकाल 21 अक्तूबर, 1996 को समाप्त हो गया है।

पोषाहार नीति के अधिवेश के अनुपालनार्थ खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड की अवसंरचना 1 अप्रैल, 1993 को खाद्य मंत्रालय से महिला एवं बाल विकास विभाग को अंतरित कर दी गयी जिसका उद्देश्य महिला एवं बाल विकास विभाग को सुदृढ़ बनाना था, जिसे देश में राष्ट्रीय पोषाहार नीति के कार्यान्वयन के समन्वय का मुख्य दायित्व सौंपा गया है।

अतः महिला एवं बाल विकास विभाग के पास विभिन्न विभागों के पोषाहारीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और समन्वय हेतु दो निकाय हैं। हालांकि, पिछले पांच दशकों के दौरान देश में पोषाहार के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, जैसे हीरा क्रांति जिससे भूखमरी पर काबू पाने, पोषाहारीय कमी को समाप्त करने और स्कूली बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा की कमी के कारण विद्यमान कुपोषण में भारी गिरावट आई है, तथापि कुपोषण की समस्या अभी भी बनी हुई है जहाँ तक स्कूल पूर्व बच्चों में कुपोषण का संबंध है हमारा देश नीचे से दूसरे नंबर पर है। अल्पपोषक कुपोषण की समस्या विशेषकर विटामिन ए, लौह और ज़ांकाईन की कमी से होने वाले कुपोषण की समस्या गंभीर चिंता का विषय रहा है क्योंकि इन अल्पपोषकों की थोड़ी सी कमी के कारण विकास और रोग प्रतिरोधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रमुख पोषाहारीय समस्याएं, जिनकी ओर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वे हैं :—तीन वर्ष से छोटी आयु के बच्चों में प्रोटीन

## 1. प्रस्तावना

फा. सं. 6-2/96-एन. डी.-1/तकनीकी-पोषाहार और राष्ट्रीय विकास को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाने लगा है। पर्याप्त पोषाहार के बिना किसी देश के मानव संसाधनों का सर्वोत्तम विकास नहीं किया जा सकता। किसी समुदाय का पोषाहारीय दर्जा विशेषकर उस समुदाय के छोटे बच्चों, गर्भवती और शिशुवती माताओं जैसे कमजोर वर्गों का पोषाहारीय दर्जा राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण संसूचक होता है। इन वर्गों में कुपोषण का अलग-अलग स्तर देश में रुग्णता और मृत्यु दर को प्रभावित करता है जैसे शिशु मृत्यु दर, पांच वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर जन्म के समय मृत्यु और जीवन प्रत्याशा में सभी देशों के विकास के संसूचक हैं। अतः पोषाहार राष्ट्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वपंक्ति है।

भारत सरकार ने कुपोषण को बहुआयामी समस्या को कम करने और बहु-क्षेत्रीय नीति के माध्यम से लोगों के लिए पोषण का अधिकतम स्तर प्राप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में 1993 में राष्ट्रीय पोषाहार नीति अपनाई। सरकार के विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की आवश्यकता को अनुभव करते हुए एक राष्ट्रीय पोषाहार कार्य योजना तैयार की गई जिसे पोषाहार नीति को संस्थागत बनाने के लिए एक ढांचे के रूप में अप्रैल, 1995 में जारी किया गया। इस व्यापक दस्तावेज में राष्ट्रीय पोषाहार नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने योगदान के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने वाले सरकार के चौदह संबंधित क्षेत्रों की भूमिका निश्चित की गई है।

नवम्बर, 1993 में देश में पोषाहारीय उपायों के कार्यान्वयन के कार्यों पर निगरानी रखने और उनकी समीक्षा करने के लिए तथा संबंधित विभागों की क्षेत्रीय कार्य योजनाओं में पोषाहारीय उपायों की पर्याप्तता पर विचार करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव की अध्यक्षता में विभाग में एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति का गठन किया गया। इससे 13 संबंधित क्षेत्रों के सचिव, योजना आयोग के सदस्य सचिव, भारतीय जनशिक्षा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक, एन. आई. एन. के निदेशक, सी. एफ. टी. आर. आई. मैसूर

ऊँचा कुपोषण, पैदा होने वाले शिशुओं का कम वजन, अल्प-पोषक कुपोषण और आहार से संबंधित पुराना बीमारियाँ ।

इस प्रकार कुपोषण की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है न कि केवल क्षेत्रीय समस्या इस संदर्भ में पोषाहार नीति द्वारा समर्थित बहुक्षेत्रीय नीति के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय हेतु मंच प्रदान करना तर्कसंगत है, पोषाहार संवर्धन हेतु अंतर क्षेत्रीय सहयोग के लिए मूल अपेक्षाओं में कुपोषण नियन्त्रण तथा पोषाहार संवर्धन का प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अपने दायित्व के रूप में मान्यता देना, पोषाहार संवर्धन का क्षेत्रीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग मानना तथा संबंधित क्षेत्रों द्वारा पोषाहार घटकों के कार्यान्वयन हेतु मार्ग निर्देश देना शामिल है । इसके अलावा अंतर क्षेत्रीय निकाय तभी कारगर तब तक से काम कर सकता है जब इसके पास समुचित समर्थन और सहायता से पोषाहार संवर्धन हेतु कार्रवाई का आवश्यकता के प्रति संबंधित क्षेत्रों को जानकारी देने की क्षमता हो । पोषाहारान्मुख क्षेत्रीय गतिविधियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रों को सतत् सहायता देने की आवश्यकता है । यह सहायक भूमिका राष्ट्रीय पोषाहार नीति के कार्यान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निभायी जाती है ।

राष्ट्रीय पोषाहार नीति के कार्यान्वयन को आवश्यक बल प्रदान करने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड तथा पोषाहार नीति पर अंतर मंत्रालयी समन्वयन समिति को मिलाकर महिला एवं बाल विकास विभाग में एक खाद्य एवं पोषाहार परिषद् की स्थापना की जाए ताकि यह परिषद् कुपोषण की विभिन्न संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान दे सके और पोषाहारान्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए समर्थन और सहायता प्रदान कर सके ।

## 2. खाद्य एवं पोषाहार परिषद् की भूमिका और दायित्व

राष्ट्रीय पोषाहार नीति का मूल उद्देश्य देश में सभी व्यक्तियों के लिए यथापेक्षित पोषाहार सुनिश्चन करना है । संबंधित क्षेत्रों की विकास नीतियों के मकारात्मक पोषाहारीय प्रभाव को अधिक से अधिक बनाने से लोगों के पोषाहारीय वर्ज में सुधार में भारी सहायता मिलेगी । खाद्य एवं पोषाहार परिषद् में एक ऐसा मंच प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सरकार के विभिन्न क्षेत्र एक निर्धारित समय अवधि के भीतर इन उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित कर सकेंगे । परिषद् निम्नलिखित के संबंध में सरकार को सलाह देगी और कार्य करेगी, सहायता संवर्धन और समन्वय क्रियाकलाप चलाएगी, ताकि सभी क्षेत्रीय प्रयास कुपोषण को उन्मूलन तथा सभी के लिए अभीष्ट पोषाहार सुनिश्चित करने के सामान्य उद्देश्य पर केंद्रित हों :—

- (1) देश में खाद्य और पोषाहार स्थिति का विज्ञापन जिसमें कुपोषण की समस्या की गम्भीरता की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके ।
- (2) सम्बन्धित क्षेत्रों का कुपोषण नियन्त्रण और पोषाहार संवर्धन में उनकी भूमिका के बारे में समर्थन, संचेतना और क्षमता निर्माण ।
- (3) क्षेत्रीय नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा, प्रबोधन और मूल्यांकन ।
- (4) सम्बन्धित क्षेत्रों द्वारा प्रयोग हेतु साधारण संसूचकों के आधार पर पोषाहार निगरानी प्रणाली का विकास

और जनता की पोषाहारीय स्थिति पर नीति उपायों का प्रभाव ।

- (5) सम्पूर्ण भारत में क्षेत्रीय भाषाओं में सभी स्तरों पर जन संचार माध्यमों तथा जन जागृति अभियानों को माध्यम से पोषाहार के प्रति संचेतना जागृत करना ।
- (6) बहुआयामी तथा बहुपक्षीय समग्र धीष्टकाण अपनाकर विभिन्न आयुवर्गों में व्याप्त अल्प-पोषण तथा कुपोषण का उन्मूलन करना ।
- (7) जनता द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यों के उपयोग से पूर्व खाद्य पदार्थों को सम्पुष्ट/समृद्ध करके पोषाहार सुधार के लिए नए उपायों की समीक्षा करना ।
- (8) ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें पोषाहार अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जा सके ।
- (9) घरेलू खाद्य सुरक्षा, बेहतर खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा, सुरक्षित जल आपूर्ति तथा पर्यावरणीय स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना ।
- (10) उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अन्य वह विषय जिनमें परिषद् आवश्यक, आनुवांगिक अथवा सहायक समझे ।

## 3. गठन

खाद्य एवं पोषाहार परिषद् का गठन इस प्रकार होगा :—

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. मानव संसाधन विकास मंत्री   | अध्यक्ष          |
| 2. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग<br>मानव संसाधन विकास मंत्रालय              | उपाध्यक्ष (पदेन) |
| 3. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग<br>कृषि मंत्रालय                             | सदस्य (पदेन)     |
| 4. सचिव, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति विभाग<br>खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों मंत्रालय | सदस्य (पदेन)     |
| 5. सचिव, खीनी तथा खाद्य तेल विभाग<br>खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों मंत्रालय       | सदस्य (पदेन)     |
| 6. सचिव, शिक्षा विभाग<br>मानव संसाधन विकास मंत्रालय                           | सदस्य (पदेन)     |
| 7. सचिव, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय   | सदस्य (पदेन)     |
| 8. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय                                     | सदस्य (पदेन)     |
| 9. सचिव, परिवार कल्याण विभाग<br>स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय          | सदस्य (पदेन)     |
| 10. सचिव, स्वास्थ्य विभाग<br>स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय             | सदस्य (पदेन)     |
| 11. सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  | सदस्य (पदेन)     |
| 12. सचिव, श्रम मंत्रालय   | सदस्य (पदेन)     |

13. सचिव, ग्रामीण रोजगार तथा निर्धनता उन्मूलन विभाग ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय	सदस्य (पदने)	30. डा. के. टी. आचार्य, साधन-सदस्य प्रौद्योगिकीविद् तथा अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक, बंगलूर	सदस्य
14. सचिव, शहरी विकास विभाग शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय	सदस्य (पदने)	31. डा. (श्रीमती) कमल खन्ना, निदेशक, गृह-विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
15. सचिव, कल्याण मंत्रालय	सदस्य (पदने)	32. डा. जे. एस. यादव, निदेशक, जन संचार संस्थान, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर, नई दिल्ली	सदस्य
16. सदस्य सचिव, योजना आयोग	सदस्य (पदने)	33. श्रीमती मञ्जुला कुलकर्णी, हंगेरी कालोनी, ओल्ड हवेली, हवेली, कर्नाटक	सदस्य
17. संयुक्त सचिव, (वा. वि.), निदेशक (बा. वि.) महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य (पदने)	34. तकनीकी सलाहकार (पोषाहार), महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
18. विज्जीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य (पदने)	35. संयुक्त सचिव (राष्ट्रीय पोषाहार नीति) महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय	सदस्य
19. महानिदेशक, भारतीय शिक्षा अनुसन्धान परिषद्	सदस्य (पदने)	अध्यक्ष किसी सरकारी/गैर-सरकारी सदस्य/सदस्यों को साक्ष्य एवं पोषाहार परिषद् की बैठकों के लिए सहयोगित कर सकता है। समय-समय पर आध्यक्षता के आधार पर यह परिषद् समितियों का गठन कर सकती है तथा उपयुक्त समझे जाने वाले अधिकारों का प्रत्याख्यान भी इन समितियों को कर सकती है।	
20. निदेशक, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान हैदराबाद	सदस्य (पदने)		
21. निदेशक, सी. एफ. टी. आर. आई., मैसूर	सदस्य (पदने)		
22. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन	सदस्य (पदने)		
23. सलाहकार (समाज कल्याण तथा पोषाहार) योजना आयोग	सदस्य (पदने)		
24. बागवानी आगुक्त, कृषि मंत्रालय	सदस्य (पदने)	महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति परिषद् की सेवाएं प्रदान करेगी तथा क्षेत्रीय मामलों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों तथा नीतियों की वार्षिक आधार पर पुनरीक्षा करेगी। इस समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-	
25. डा. एन. ए. डी. परिप्या, पूर्व-निदेशक, सी. एफ. टी. आर. आई. सूर्यकान्ति, 333 हिकल, मैसूर	सदस्य (पदने)		
26. डा. श्रीमती राजमल पी. दवेवास, कुलपति, श्री जिनमोशिलगम् डीपड वृत्तिविस्ती, कायम्बटूर	सदस्य (पदने)		
27. डा. (श्रीमती) मृणालिनी देवी पुआर कुलपति, एम. एस. विश्वविद्यालय, बकाला	सदस्य		
28. डा. कल्याण बागची, निदेशक पोषाहार सिंडिकेट, नई दिल्ली	सदस्य		
29. डा. एन. के. अरांडा, अपर प्रोफेसर (बाल शिक्षा) अखिल भारतीय आधुनिकता संस्थान नई दिल्ली	सदस्य	(1) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	अध्यक्ष
		(2) सचिव, कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय	सदस्य
		(3) सचिव, शिक्षा विभाग	सदस्य
		(4) सचिव, परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
		(5) सचिव, कल्याण मंत्रालय	सदस्य
		(6) सचिव, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य

- (7) सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सदस्य
- (8) संयुक्त सचिव (रा. पो. बी.) महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य
- (9) संयुक्त सचिव, (बा. वि.) महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य
- (10) निदेशक, रा. पो. संस्थान हैदराबाद सदस्य
- (11) तकनीकी सलाहकार (पोषाहार) सदस्य-सचिव

#### 4. परिषद् का दर्जा तथा अधिकार

खाद्य एवं पोषाहार परिषद् एवं गैर सार्वजनिक उच्चाधिकार प्राप्त समिति होंगी और इसके पास वित्तीय, प्रशासकीय तथा अन्य मूर्तों से सम्बन्धित ऐसे अधिकार होंगे, जो उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्याभूति प्राप्त किये जायेंगे। मंत्रालय की वित्तीय शक्तियों से अधिक के मामलों में जहाँ वित्त मंत्रालय की सहमति आवश्यक हो, सदस्य, वित्त मंत्रालय की ओर से अपनी सहमति देंगे।

#### 5. परिषद् का सचिवालयी तथा कार्यकारी स्क्व

महिला एवं बाल विकास विभाग की मौजूदा खाद्य एवं पोषाहार बौद्ध (प्रभाग) को इस प्रकार से सुदृढ़ तथा पुनर्गठित किया जायेगा, ताकि वह खाद्य एवं पोषाहार परिषद् की सचिवालयी तथा कार्यकारी दल की सहायता उपलब्ध करवा सके। संयुक्त सचिव (रा. पो. का.) परिषद् के सदस्य सचिव होंगे तथा एक प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य कर्मिकों द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जायेगी।

#### 6. कार्य व्यवहार

खाद्य एवं पोषाहार परिषद् की बैठकें एक साल में एक या दो बार होंगी। परिषद् सभी योजनाओं तथा कार्य नीतियों को पोषाहारीय पक्षों तथा तकनीकी मामलों पर विचार विमर्श करेगी तथा उनका निपटारा करेगी। समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये

जाने वाले मामलों के संबंध में सरकार की अपेक्षा हो सकती है कि उनके लिये पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाये तथा समय-समय पर सरकार द्वारा दिये जाने वाले निदेशों तथा अनुदेशों के अनुसार ही परिषद् अपने कार्यकलापों का निष्पादन करेगी।

#### 7. परिषद् के निर्णय तथा आदेश

परिषद् के निर्णय, आदेश, स्वीकृतियाँ, अनुदेश आदि सदस्य-सचिव के हस्ताक्षरों से ही प्रेषित किये जायेंगे या फिर ये हस्ताक्षर एक अधिकारी द्वारा किये जा सकते हैं जिसके लिये विभाग उसे विधिवत रूप से नामित करे।

#### 8. बजट

परिषद् के विभिन्न क्रियाकलापों, परिषद् की बैठकों में सदस्यों द्वारा भाग लेने पर होने वाला व्यय 'राष्ट्रीय पोषाहार नीति का कार्यान्वयन' नामक योजना (स्कीम) के अन्तर्गत किया जायेगा, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के खाद्य पोषाहार बौद्ध के समग्र बजट का एक भाग होगा।

#### 9. कार्यकाल

परिषद् का कार्यकाल इस संकल्प के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जन सामान्य की जानकारी के लिये इस संकल्प की भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

डा. (श्रीमती) रेखा भार्गव  
संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 20th October 1997

#### RESOLUTION

##### I. Preamble

F. No. 6-2/96-ND.I/Tech.—Nutrition and national development are increasingly being recognised as two sides of the same coin. Without adequate nutrition, the development of human resources of a country can not be at its best. The nutritional status of a community, particularly of its vulnerable groups comprising young children, expectant and nursing mothers serves as an important indicator of national development. The varying degrees of malnutrition in these groups influence morbidity and mortality rates in the country such as infant mortality rate, mortality under-five years, maternal mortality rate, crude death rate and life expectancy

at birth the indicators which reflect the development of a country. Thus "nutrition" emerges as one of the most important pre-requisites for national development.

The Government of India adopted the National Nutrition Policy in 1993 under the aegis of the Department of Women and Child Development for alleviating multi-faceted problem of malnutrition and achieving the optimal state of nutrition for the people through a multisectoral strategy. Recognising the need of a series of actions to be undertaken by the various concerned Departments of the Government, a National Plan of Action on Nutrition was developed and released in April, 1995 to serve as a framework for institutionalising the Nutrition Policy. This comprehensive document identifies the role of as many as 14 concerned sectors of the Government considered important for their contribution towards achieving the goals of the Nutrition Policy.

An Inter-Ministerial Coordination Committee was constituted in the Department in November, 1993, under the chairmanship of Secretary, Department of Women and Child Development, to oversee and review the implementation of nutrition intervention measures in the country and also the

adequacy of nutritional considerations in the sectoral plans of action of the related Departments. It has membership of Secretaries of 13 concerned sectors; Member-Secretary, Planning Commission; Director-General, ICMR; Director, NIN; Director, CFTRI, Mysore; and the Chief Executive Officer, NNSO.

The Department also has a non-statutory, high powered Advisory committee called Food and Nutrition Board (FNB), established vide Resolution No. 6(10)/63-Tech.I dated 24-4-1964, published in the Gazette of India, and is functioning under the chairmanship of Secretary (WCD). The subsidiary Food and Nutrition Wing of the Department of Food during 1963-64 reorganised into Food and Nutrition Board (Division) served as the secretariat and the executive arm of the Food and Nutrition Board (Committee). The FNB has been reconstituted from time to time and its functions redefined according to the needs of that time. The Board was last reconstituted in 1993, the term of which has expired on 21st October, 1996.

The Infrastructure of the Food and Nutrition Board was transferred from Ministry of Food to the Department of Women and Child Development on 1st April, 1993 in pursuance of the mandate of the Nutrition Policy. The objective was to strengthen the Department of Women and Child Development which has the nodal responsibility of coordinating the implementation of National Nutrition Policy in the country.

The Department of Women and Child Development thus has two bodies to review and coordinate the implementation of nutrition intervention programmes of various Departments. Though the achievements on nutrition scene in the country during the last five decades have been noteworthy in terms of the "Green Revolution" helping to overcome famines, in targeting the classical nutritional deficiency syndromes, and in achieving a striking decline in the prevalence of severe protein energy malnutrition among pre-school children, malnutrition continues unabated. The country ranks second from the bottom as far as prevalence of malnutrition among pre-school children is concerned. The problem of micronutrient malnutrition, particularly relating to deficiencies of vitamin A, Iron and iodine has been a matter of serious concern since even the milder deficiency states of these micronutrients lead to adverse consequences in growth, development and immunity. The major nutritional problems requiring focused attention are protein energy malnutrition among children under the age of three years, low birth weight of new borns, micronutrient malnutrition and emerging incidence of diet related chronic disorders.

The problem of malnutrition, therefore, emerges as a national problem and not merely a sectoral problem. In this context, it is pertinent to provide a platform for inter-sectoral coordination to facilitate the operationalisation of the multi-sectoral strategy advocated by Nutrition Policy. The basic requirements for inter-sectoral collaboration for nutrition promotion include recognition of malnutrition control and nutrition promotion by each concerned sector as its responsibility, adoption of nutrition promotion as an important area of sectoral programming, and guidance for implementation of nutrition components by concerned sectors. Further, the inter-sectoral body can function effectively only when it has the capacity to sensitize the concerned sectors towards the need for action for nutrition promotion with proper support and assistance. A continued support to sectors for developing and implementing nutrition oriented sectoral activities is needed. This support role has to be played by the nodal Department of Women and Child Development for implementation of the National Nutrition Policy.

In order to give the necessary thrust to the implementation of the National Nutrition Policy, it has, therefore, been decided to establish a Food and Nutrition Council in the Department of Women and Child Development by amalgamating the existing Food and Nutrition Board and the Inter-ministerial Coordination Committee on Nutrition Policy in order that it could pay exclusive attention to the various connected problems of malnutrition and provide support and assistance for implementation of nutrition oriented sectoral programmes.

## II. Role and responsibilities of the Food and Nutrition Council

The National Nutrition Policy basically aims at ensuring optimum nutrition for all individuals in the country. Maximising the positive nutritional impacts of development policies of the concerned sectors can significantly contribute to improving nutritional status of the people. The Food and Nutrition Council will provide a forum through which the different sectors of the Government will ensure the fulfilment of these objectives within a set time frame. The Council will advise the Government and undertake, aid, promote and co-ordinate activities in regard to the following so that all sectoral efforts converge towards the common aim of elimination of malnutrition and ensuring optimum nutrition for all :—

- (i) Situational analysis of food and nutrition situation in the country providing a clear understanding of the magnitude of the problem of malnutrition in a disaggregated manner.
- (ii) Advocacy, sensitisation and capacity building of the concerned sectors regarding their role in malnutrition control and nutrition promotion;
- (iii) Review, monitoring and evaluation of sectoral strategies and programmes;
- (iv) Development of Nutrition Surveillance System based on simple indicators for use by concerned sectors and over-viewing the impact of policy measures on the nutritional status of the population;
- (v) Creation of nutritional awareness at all levels through nutrition education and training, mass media communication and mass awareness campaigns in regional languages throughout India;
- (vi) Elimination of micronutrient malnutrition in different age groups adopting a holistic approach which is multidimensional and multisectoral.
- (vii) Review of new interventions for nutrition improvement of the population like food fortification/enrichment before its adoption at the national level;
- (viii) Identification of specific areas in which nutrition research could be encouraged;
- (ix) Measures for ensuring household food security, improved food quality and safety, safe water supply and environmental sanitation.
- (x) Such other matters as the Council may consider necessary, incidental or conducive to the attainment of above objects.

## III. Composition

The composition of the Food and Nutrition Council will be as follows :

1. Minister for Human Resource Development.

Chairman

2. Secretary, Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development.

Vice-chairperson

(ex-officio)

3. Secretary, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture.

Members

(ex-officio)

4. Secretary, Department of Food and Civil Supplies, Ministry of Food and Consumer Affairs.
5. Secretary, Department of Sugar and Edible Oils, Ministry of Food and Consumer Affairs.

**Members  
(ex-officio)**

6. Secretary, Department of Education, Ministry of Human Resource Development.
7. Secretary, Ministry of Environment and Forests.
8. Secretary, Ministry of Food Processing Industries.
9. Secretary, Department of Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare.
10. Secretary, Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare.
11. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.
12. Secretary, Ministry of Labour.
13. Secretary, Department of Rural Employment and Poverty Alleviation Ministry of Rural Areas and Employment.
14. Secretary, Department of Urban Development, Ministry of Urban Affairs and Employment.
15. Secretary, Ministry of Welfare.
16. Member-Secretary, Planning Commission.
17. Joint Secretary (CD)/Director(CD) Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development.
18. Financial Adviser, Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development.
19. Director-General, Indian Council of Medical Research.
20. Director, National Institute of Nutrition, Hyderabad.
21. Director, CFTRI, Mysore.
22. Chief Executive Officer, National Sample Survey Organisation.
23. Adviser (Social Welfare & Nutrition) Planning Commission.
24. Horticulture Commissioner, Ministry of Agriculture.
25. Dr. H.A.B. Parpia, Ex-Director, CFTRI, Suryakanti, 333 Hinkal, Mysore.
26. Dr. (Mrs.) Rajammal P. Devadas, Chancellor, Sri Avinashilingam Deemed University, Coimbatore.
27. Dr. (Mrs.) Mrunalini Devi Puar, Chancellor, M. S. University, Baroda.
28. Dr. Kalyan Bagchi, Director, Nutrition Syndicate, New Delhi.
29. Dr. N. K. Arora, Additional Professor (Paediatrics), AIIMS, New Delhi.
30. Dr. K. T. Achaya, Food Technologist and Emeritus Scientist, Bangalore.

**Members**

31. Dr. (Mrs.) Kumud Khanna, Director, Faculty of Home Science, Delhi University, Delhi.
32. Dr. J. S. Yadav, Director, Institute of Mass Communication, J.N.U., New Campus, New Delhi.
33. Smt. Manjula Kulkarni, Hegari Colony, O'd Hubli, Hubli, Karnataka.
34. Technical Adviser (Nutrition), Department of Women and Child Development.

**Member-Secretary**

35. Joint Secretary (National Nutrition Policy) Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development.

The Chairperson may co-opt any other official(s) or non-official(s) as member(s) of the Food and Nutrition Council for any of its meetings. The Council may constitute such committees as it may deem necessary from time to time and delegate such powers to these committees as it may consider appropriate.

An Executive Committee under the chairpersonship of Secretary, Department of Women and Child Development will be constituted to service the Council and to review the policies and programmes being implemented by the various sectoral Ministries on a quarterly basis. The constitution of this Committee will be as follows:

**CHAIRPERSON**

1. Secretary Department of Women and Child Development.

**MEMBERS**

2. Secretary, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture.
3. Secretary, Department of Education.
4. Secretary, Department of Family Welfare.
5. Secretary, Ministry of Welfare.
6. Secretary, Department of Health.
7. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.
8. Joint Secretary (NNP), Department of Women and Child Development.
9. Joint Secretary (CD), Department of Women and Child Development.
10. Director, NIN, Hyderabad.

**MEMBER-SECRETARY**

11. Technical Adviser (Nutrition).

**IV. Status and Powers of the Council**

The Food and Nutrition Council will be a non-statutory high powered committee and will exercise such powers as may be delegated to it by the Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, with regard to financial, administrative and other matters. In respect of matters exceeding the financial powers of a Ministry and requiring the concurrence of the Ministry of Finance, the Member (Finance) shall communicate the concurrence on behalf of the Ministry of Finance.



**V. Secretariat and Executive Arm of the Council**

The existing Food and Nutrition Board (Division) of the Department of Women and Child Development will be suitably strengthened and reorganised to serve as the secretariat and the executive arm of the Food and Nutrition Council. The Joint Secretary (NNP) will be the Member Secretary of the Council and will be assisted by an Administrative Officer and such other staff as may be found necessary.

**VI. Transaction of Business**

The Food and Nutrition Council would normally meet once or twice a year. The Council will discuss and resolve the technical issues and nutritional aspects of all the plans and strategies.

In exercise of its functions, the Council shall be subject to such directions and instructions as Government may issue from time to time and Government may require its prior approval to be obtained in respect of such matters as it may specify from time to time.

**VII. Decisions and orders of the Council**

The Council's decisions, orders, sanctions, instructions etc., shall be communicated under the signatures of the Member Secretary of the Council or any other officer of the Department duly nominated for this purpose.

**VIII. Budget**

The expenditure on various activities of the Council, on participation of Members in its meetings will be met under the Plan Scheme viz., 'Implementation of National Nutrition Policy' which will form a part of the total budget of the Food and Nutrition Board of the Department of Women and Child Development.

**IX. Tenure**

The tenure of the Council will be three years with effect from the date of publication of this Resolution in the Gazette.

**ORDERS**

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that this resolution be published in the Gazette of India for general information.

DR. (SMT.) REKHA BHARGAVA  
Jt. Secy.

